भारतीय जनता पार्टी
मोदी सरकार 2.0
का पहला साल

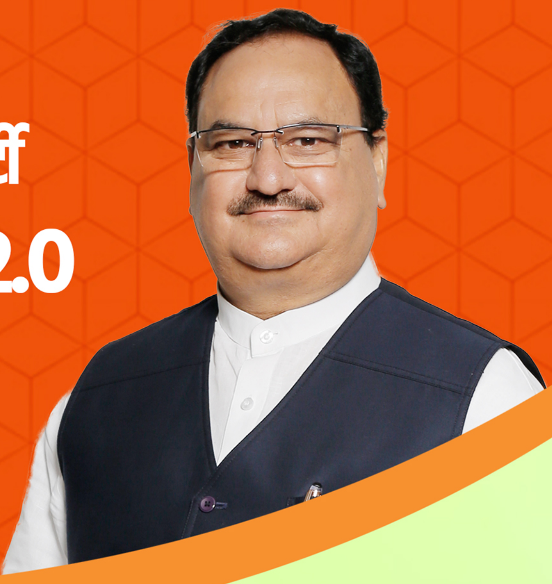

मोदी सरकार 2.0 का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रभावशाली इसलिए कि जनादेश, शासन की गति, सरकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, मजबूत बुनियादी ढांचा और दशकों से लटके हुए मुद्दों के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी गई। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि कोविड-19 और अम्फान चक्रवात ने जो अभूतपूर्व संकट खड़े किए, उससे दु:ख और विपदा तो आई ही साथ ही भारी नुकसान हुआ। लेकिन आज देश में एक निर्णय लेने वाली उत्तरदायी सरकार है, जो देशवासियों के लिए फिक्रमंद है, साथ ही जिसके पास दृष्टि और दूरदर्शिता है, जो इस चुनौतीपूर्ण समय से देश को बाहर निकालने का सामर्थ्य रखती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बाद भारत निश्चित ही इस कठिन समय से बाहर आ जाएगा। साथ ही, देश ने सहकारी संघवाद के बेहतरीन उदाहरण को क्रियान्वित होते हुए भी देखा है, लेकिन अब हमें बगैर चूके प्रत्येक नागरिक को, उसके द्वारा इस कठिन स्थिति को समझने और सर्वोत्तम आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, धन्यवाद देना है। आने वाले दिनों में यह देश, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ऐतिहासिक निर्णय

- **अनुच्छेद 370 हटा: दो नये केंद्रशासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने :** जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का कलंक हटा और राज्य में तीव्र विकास के रास्ते खुले। दो नये केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए।

- **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 :** अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान।

- **राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त :** उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा कर दी।

- **तीन तलाक :** मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक में अपनी राय दी। सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर निर्णय से आज करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा के कलंक से मुक्त हो खुली हवा में सांस ले रही हैं। इस संबंध में मोदी सरकार ने तीन तलाक की कुप्रथा पर कड़ा कानून 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019' बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण किया।

- **करतारपुर गलियारा राष्ट्र को समर्पित :** करतारपुर गलियारे की चेक पोस्ट शुरू हो जाने से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहेब जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा।

- **ब्रू-रियांग समझौता :** इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों से चल रही बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हुआ और करीब 34 हजार व्यक्तियों को त्रिपुरा में बसाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- **बोडो समझौता :** ऐतिहासिक बोडो समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा।

सेना के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

- प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति : रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों का एक नया विभाग बनाया और जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) प्रमुख नियुक्त किए गए है।
- वायुसेना में शामिल हुए आठ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर : अपाचे हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ गई है।
- भारत ने फ्रांस से पहला राफेल विमान 8 अक्टूबर को प्राप्त किया। फ्रांस से खरीदे गये 36 राफेल लड़ाकू विमानों की श्रृंखला में प्रथम विमान सौंपे जाने के समारोह का आयोजन फ्रांस में राफेल विमान निर्माता दसॉल्ट एविएशन के प्रतिष्ठान में किया गया।

अन्य प्रमुख उपलब्धियां

- 'आयुष्मान भारत' के तहत एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थी : भारत ने 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान कर इस दिशा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।
- अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे : अटल पेंशन योजना ने 2.23 करोड़ लोगों का नाम दर्ज कर असाधारण कार्य किया।
- 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट': भारत ने 142वें पायदान से छलांग लगाकर 63वें पायदान पर जगह बना ली है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 14.5 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित : संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर करने का निर्णय लिया गया है।
- 10 बैंकों के विलय से बने चार बड़े बैंक : सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
- दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक : 40 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
- बीएसएनएल, एमटीएनएल का विलय : 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी।
- राष्ट्रहित में किया आरसेप से किनारा: भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप को खारिज कर दिया।
- अटल भूजल योजना' की शुरुआत : सात राज्यों के 8,350 गांवों को फायदा होगा।
- लेह और मनाली को जोड़ने वाली सुरंग का नामकरण 'अटल टनल' करने की घोषणा हुई।
- 10,000 नए एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन हेतु 'कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन' को मंजूरी।

आत्मनिर्भर भारत

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा

- 80 करोड़ गरीबों को कुल पांच महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं/चावल और प्रति परिवार को एक किलो दाल मुफ्त
- 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रुपये
- मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन, 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित
- 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि
- सरकार वर्तमान 'पीएम किसान योजना' के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये, 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित
- केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को 'भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष' का उपयोग करने के आदेश दिए हैं

कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कदम

- फार्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष
- सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के जरिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपये
- कृषि क्षेत्र केंद्रित गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार के लिए उपाय
- किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
- पंचायतों का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफार्म ई-ग्राम स्वराज ऐप लॉन्च। इसमें पंचायत के विकास कार्यों, उसके फंड और कामकाज की जानकारियां हर व्यक्ति को मिलेगी।
- ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी सरकार द्वारा शुरु की गई स्वामित्व योजना।

एमएसएमई को भारी राहत

- एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा
- 'एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स' के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी
- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं
- डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी

प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम

- 'शिशु मुद्रा' के तहत कर्ज लेने वालों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी- 1500 करोड़ रुपये की राहत
- प्रति रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को 10 हजार रुपये तक की ऋण सुविधा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रोत्साहन

संरचनात्मक सुधार

- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत, विविध अवसर, उदार व्यवस्था, खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना और नीतिगत सुधार
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
- रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा की राशि को 60,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये किया गया
- एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति

कोविड-19 संकट और प्रबंधन

'जनता कर्फ्यू'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर पूरे देश ने 22 मार्च, 2020 को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक देश में 'जनता कर्फ्यू' का पालन किया। उसी दिन शाम 5 बजे राष्ट्र की निःस्वार्थ सेवा करने वाले डॉक्टर, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं सुरक्षाकर्मियों को पूरे देश ने घर से बाहर निकल कर ताली, थाली व शंख-घंटी आदि बजाकर धन्यवाद किया।

'जान है तो जहान है'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च, 2020 को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च, 2020 की आधी रात से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की।

लॉकडाउन से पहले 1444 देशी और विदेशी नागरिकों को बचाया

भारत ने मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका जैसे देशों के 48 नागरिकों को भी सुरक्षित बचाने का काम किया।

30 देशों में फंसे 72,500 से अधिक नागरिकों को बचाया

भारत ने 'वंदे भारत' और 'समुद्र सेतु' मिशन के पहले दो चरणों के दौरान बड़े पैमाने पर 30 से अधिक देशों में फंसे 72,500 से अधिक नागरिकों को वापस लाने का काम किया।

प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें

28 मई, 2020 तक 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 52 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक भेजा जा चुका है।

जनवरी में 1 परीक्षण प्रयोगशाला से बढ़कर अब 610 हुईं

25 मई तक भारत में 610 परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं, जनवरी, 2020 में देश में केवल 01 परीक्षण प्रयोगशाला थी।

भारत का कोविड-19 मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है

26 मई, 2020 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर 2.87 प्रतिशत है, जो दुनिया भर में सबसे कम है। समय पर लॉकडाउन, जल्दी जांच और कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का प्रबंधन कम मौत का मुख्य कारण है।

विश्व में 4.5 मौतों के मुकाबले भारत में प्रति लाख 0.3 मौतें

वैश्विक स्तर पर 4.5 मौतों के मुकाबले भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 0.3 मौतें हुई हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। यह लॉकडाउन, समय पर जांच और कोविड-19 मामलों के बेहतर प्रबंधन के कारण हुआ है।

केंद्र सरकार ने 'आरोग्य सेतु' ऐप लॉन्च किया

केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य सेतु' ऐप लॉन्च किया गया जिसे अब तक 11.74 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउललोड किया है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना संक्रमण से खुद को होने वाले जोखिम का आकलन करने में सक्षम बनाता है।

भारत ने 120 से अधिक देशों को दवाएं भेजीं

भारत, जिसे 'विश्व की फार्मेसी' माना जाता है, ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 120 से अधिक देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा भेजीं।

6.39% कोविड-19 मामले में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता, रिकवरी दर लगभग 42% हुई

25 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल कोविड रोगियों में से लगभग 42 प्रतिशत ठीक हो गए हैं। भारत में केवल 6.39 प्रतिशत मरीजों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक स्तर पर, प्रति लाख में 62 लोग संक्रमित हैं और भारत में यह आंकड़ा 7.9 पर है।

शून्य' से लेकर अब भारत प्रतिदिन 3 लाख से अधिक पीपीई किट और एन95 मास्क का उत्पादन कर रहा है

भारत में फरवरी 2020 में शून्य उत्पादन से आज मई के मध्य तक प्रतिदिन 3 लाख से अधिक पीपीई किट और इतनी ही संख्या में एन 95 मास्क का उत्पादन हो रहा है।

मोदी सरकार 2.0 के पहले वर्ष की उपलब्धियां, जिस संवेदना और मजबूती के साथ COVID-19 को संभाला गया और 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज, इन सबके साथ अब हमारा देश कोविड के बाद की दुनिया में मिलने वाले अवसरों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर देशवासी को सुरक्षित और सशक्त बनाने की हमारी इस यात्रा में आप भी सहयात्री बनिए ताकि हर नागरिक अपनी परिस्थिति से उठकर नए भारत का ध्वजवाहक बन सके।

फेस कवर पहनिए, सुरक्षित रहिए
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए